फाइल नं0-71-1099/12/2021

111/2023/1/363838/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,

उप सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 07 अगस्त, 2023

**विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में 100 यू0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत लेक्चर थियेटर भवन के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदया,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-यू014017/146/2019-एमई-।।/8035777, दिनांक 25.08.2022 द्वारा **केन्द्र पुरोनिधानित योजना** के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेजो में एम0बी0बी0एस0 (यू0जी0) सीटों की वृद्धि पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में 100 यू0जी0 सीटों की वृद्धि करते हुए रू0 120.00 करोड़ की लागत अनुमोदित की गयी। उक्त योजना का फ़ण्डिग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश+राज्यांश) है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-57/2023/1/296217/2023-71-1002/15/2022, दिनांक 30.03.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत रू0 120.00 करोड़ के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में रू0 19.87 करोड़ एंव राज्यांश के रूप में रू0 13.25 करोड़ अर्थात् कुल रू0 33.12 करोड़ की धनराशि महानिदेशक, चि0शि0 एंव प्रशि0 के निर्वतन पर रखी गयी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में 100 यू0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत लेक्चर थियेटर भवन के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 554.05 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **रू0 277.00 लाख (रू0 दो करोड़ सतहत्तर लाख मात्र)** (रू0 177.00 लाख केन्द्रांश+रू0 100.00 लाख राज्यांश) की धनराशि उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30.03.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु यू0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष केन्द्रांश एंव राज्यांश के रूप में रक्षित धनराशि कुल रू0 33.22 करोड़ में से पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते में हस्तान्तरित किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों**

1. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।
2. प्रायोजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
3. प्रायोजना प्रस्ताव में केन्द्रीय वातानूकूलन , एक्वास्टिकल वाल पैनलिंग , लेक्चर थियेटर हेतु साउण्ड ब्लाक कम्पोजिट सीलिंग पैनल , स्टेज हेतु टीक वुड फ्लोरिंग , सिन्थेटिक कारपेट फ्लोरिंग का प्राविधान किया गया है , जो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है।
4. प्रायोजना का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी जनपद-मेरठ की वर्ष 2022 की अनुसूची दरों के आधार पर प्रस्तावित की गयी है तथा जो दरें इसमें उपलब्ध नहीं है , उन्हें बाजार दरों एंव डी0एस0आर0 2021 के आधार पर प्रस्तावित की गयी है।
5. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर लागत आंकलित की गयी है। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो तथा जी0एस0टी0 का भुगतान वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित लेक्चर थियेटर चेयर , सी0सी0टी0वी0 सिस्टम , एसेस कन्ट्रोल सिस्टम , लेन सिस्टम , आडियो व वीडियो सिस्टम , साउण्ड , स्टेज लाइटिंग , स्टेज कर्टेन सिस्टम , पी0ए0 सिस्टम , प्राजेक्शन सिस्टम की लागत को इंडीकेटिव दरें मानते हुए परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एंव स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाए।
7. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु एकमुश्त लागत रू0 5.00 लाख प्रस्तावित की गयी है। अतः निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत संयोजन हेतु विद्युत विभाग से विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाए तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय।
8. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत् मानते हुए मात्र लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।
9. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।
10. प्रायोजनान्तर्गत प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है , जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एंव अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12. भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनॉक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
15. कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक /प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
16. प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा , जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
18. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
19. संबंधित परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

( एस0 पी0 सिंह )
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
4. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट कंसट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलमेंट कारपोरेश्न (उ0प्र0 समाज कल्याण निगम लि0) लखनऊ।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।